

प्रेस विज्ञप्ति

निष्क्रिय क.भ.नि. खातों के निपटान के लिए ऑनलाइन हैल्पडैस्क

बंडारू दत्तात्रेय द्वारा निष्क्रिय खातों के लिए ऑनलाइन हैल्पडैस्क का शुभारंभ

निष्क्रिय खातों की पहचान तथा निपटान के लिए अभियान का शुभारंभ

मुख्यालय, नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2015 : 'श्रमेव जयते' कार्यक्रम के अवसर पर क.भ.नि. निष्क्रिय खाते जिनमें 27000 करोड़ रु. शेष हैं के निपटान के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इनकी वसूली के लिए एक क्रियात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया है। श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने आज निष्क्रिय खातों के खाताधारकों को अपने खातों का पता लगाने और वर्तमान खाते में इनके निपटान अथवा अंतरण के लिए उन्हें सहायता करने के लिए एक क.भ.नि.सं. निष्क्रिय खाता ऑनलाइन हैल्पडैस्क का उद्घाटन किया।

ऑनलाइन हैल्पडैस्क पर क.भ.नि.सं. की वेबसाइट के द्वारा पहुंचा जा सकता है। सदस्य को स्थापना कोड, भविष्य निधि खाता संख्या, पता, राज्य, शहर, कार्यग्रहण की तिथि आदि को सम्मिलित करते हुए अपने रोजगार के ज्ञात विवरण को विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोफार्मा में उपलब्ध कराने के लिए कहा जाएगा। उसी प्रकार से व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, मोबाइल नं., जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, ई-मेल आई.डी., संपर्क करने का पता, आधार नं., बैंक खाता सं. आदि को भी उपलब्ध कराया जाना है। सदस्यों से जिस सीमा तक सूचना उनके पास उपलब्ध है, उसे प्रदान करने की आशा की जाती है। इसके पश्चात् भविष्य में संदर्भ तथा ट्रैकिंग के लिए एक संदर्भ आई.डी. बनाई जाएगी। बनाई गई संदर्भ आई.डी., के आधार पर संबंधित फील्ड कार्यालय (जहां सदस्य का भविष्य निधि खाता है) सदस्य से संपर्क करेगा और खाते के निपटान अथवा अंतरण के लिए जैसा भी मामला हो, उसका मार्गदर्शन करेगा।

यूनिवर्सल खाता संख्या (यू.ए.एन.) की शुरुआत होने से उपर्युक्त पहल के और सुविधाजनक होने की आशा है क्योंकि यू.ए.एन. से बहुत सी पूर्व भविष्य निधि खाता संख्याओं का वर्तमान खाते से समेकन हो सकेगा। इसके अतिरिक्त क.भ.नि.सं. के हाल ही के ई-गवर्नेंस पहल जैसे कि ऑनलाइन अंतरण टावा पोर्टल, अंशधारकों के वार्षिक खातों को अद्यतन करने के लिए बैच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत किए जाने से संगठन को निष्क्रिय खातों को शून्य करने तथा आवश्यक निवारक कार्रवाई करने में सहायता मिली है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, क.भ.नि.स ने अपने पीएनड कार्यालयों को यह निर्देश जारी किया है कि पहचान करने तथा निष्क्रिय खातों को पहचानकर, निपटान की सुविधा देने के लिए कैम्प आयोजित किए जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वास्तविक दावेदार को पैसे प्राप्त हों। इस पहल में अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए नियोजताओं की भागीदारी भी मांगी गई है तथा वर्तमान पता, वर्तमान रोजगार, सदस्य को यू ए एन आर्बाइल है या नहीं, बैंक खाता विवरण, सदस्य का आधार कार्ड विवरण सहित लाभकर्ताओं की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

क.भ.नि.स की हाल ही की ई-गवर्नेंस पहल

• निष्क्रिय खाता हेल्पडेस्क	आज
• नया पास बुक (यूएन आधारित)	10/2014
• मासिक लेन देन के लिए सदस्य एवं नियोजताओं को एसएमएस	10/2014
• यूनिवर्सल खाता सख्या कार्यक्रम	10/2014
• स्थापनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण (ओ.एन.आर.ई. पोर्टल)	06/2014
• अनुपालन संबंधी प्रकर्यों की केंद्रीकृत मॉनीटरिंग	03/2014
• फूटप्रान्त स्थापनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक-रिटर्न	01/2014
• ऑनलाइन ट्रांसफर दावा पोर्टल	10/2013
• वार्षिक ब्याज (बैंचवारी) की ऑटो क्रेडिटिंग	08/2013
• अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए कवरेज का प्रमाण-पत्र	08/2013
• सदस्यों के लुप्त विवरण संबंधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न	03/2013

PRESS RELEASE

Online helpdesk for settlement of Inoperative EPF Accounts

Bandaru Dattatreya launches online helpdesk for Inoperative Accounts

Campaign for identification and settlement of Inoperative Accounts launched

Head Office, New Delhi, 18th February, 2015: In accordance with the Hon'ble Prime Minister's directions on the occasion of the 'Shrameva Jayate' programme regarding the settlement of EPF Inoperative Accounts having Rs. 27,000 crores as balance, EPFO has launched an action programme for realizing the same. Shri Bandaru Dattatreya, Hon'ble Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge) today inaugurated an **EPFO Inoperative Account online helpdesk** to assist the holders of Inoperative Accounts to trace out their accounts and effect settlement or transfer of the same to their present account.

The online helpdesk can be accessed through EPFO's website. The member shall be prompted to provide the known details of his/her employment in a specially designed proforma including establishment code, PF account no. address, State, City, date of joining etc. Likewise, personal information is also to be provided like name, mobile number, Date of Birth, Name of Father / Husband, e-mail Id, contact address, Aadhar number, Bank A/c No. etc. The members are expected to provide the information to the extent available with them. Thereafter, a reference ID is created for future reference and tracking. Based on the reference ID generated, the field office concerned (where the member held his PF account) shall contact the member and guide him for getting the settlement or effecting the transfer as the case may be.

The introduction of Universal Account Number (UAN) is expected to greatly facilitate the above initiative as UAN would enable consolidation of multiple previous PF account numbers with the present one. In addition to this, the recent e-governance initiative of EPFO such as Online Transfer Claim portal (OTCP), the introduction of batch processing software for updating the annual accounts of the subscribers have helped the organization to zero-in on the Inoperative Accounts and take necessary corrective action.

In addition to the above, EPFO has issued directions to the field formations to organize camps, to identify and facilitate settlement of Inoperative Accounts and ensure that the money goes to the rightful claimant. The participation of employers covered under the Act in this initiative has been sought and all efforts are being taken to ascertain the present status of the beneficiaries including the current address, current employment, whether the member is a UAN allottee, the bank account details and Aadhar details of the member.

Recent e-governance initiative of EPFO

- | | |
|--|---------|
| • Inoperative Accounts helpdesk | TODAY |
| • New passbook (UAN based) | 10/2014 |
| • SMS to member & employers for monthly transactions | 10/2014 |
| • Universal Account Number programme | 10/2014 |
| • Online Registration of establishment (OLRE portal) | 06/2014 |
| • Centralized monitoring of the compliance related functions | 03/2014 |
| • Electronic-return for exempted establishment | 01/2014 |
| • Online transfer claim portal | 10/2013 |
| • Auto crediting of annual interest (Batch wise) | 08/2013 |
| • Certificate of coverage for International Workers | 08/2013 |
| • Electronic return to collect missing details of members | 03/2013 |